and that is why I have struck a hopeful note in so far as some bilateral matters are concerned but it remains to be seen how quickly, and to what extent we put these decisions into action.

Then, Sir, I have reported only about the talks which took place between Mr. Agha Shahi and myself and Mr. Agha Shahi and our Prime Minister. I had no occasion to bring in what a third person said—whether it is a Congressman from America or leader from Timbuktu. It is difficult to bring in matters like that. Therefore, I have confined my attention to the talks that took place. So, I cannot say anything and comment on anything said elsewhere as the hon'ble Member has said. I only said what Mr. Agha Shahi told me. That is what I have reported. I have not gone into the whole question of what we have to think about what he said to us. That is entirely a different matter, Sir. Then, about the Simla spirit, I feel that whatever is possible to be decided amicably, to be settled amicably, comes under that Simla spirit, because, Simla agreement is not specific only, but it is also general—about the spirit which is mentioned in the Agreement, according to which, the relations between the two countries have to be normalised. This is of a very general nature. And if on one or two issues we cannot see eye to eye, we cannot say that the Simla agreement has broken down on those issues. We shall have to talk again and again; that is the real spirit of the Simla agreement. About my views on Mr. Agha Shahi's comment, regarding a big country like India' I did not really consider it necessary to question him on the point because we cannot do anything in respect of those fears. If India is big, it is not possible for India to oblige anybody by becoming small. That is something which nobody can help and therefore we have to take it as a part of life.

About the exchange of prisoners, as I have mentioned in my answer to a question only yesterday, which did not come up for oral answer, but which is contained in the Written Answers given, an AIDE MEMORIE was presented to us just a couple of days before Mr. Agha Shahi's visit, in which certain numbers 240 or 250 or 300 were given to us. I don't remember the exact figure. we are examining this. In return for these prisoners, an offer was made that we should exchange some prisoners, 150 or 160, who are detained in our jails here. This is a matter which will be looked into. There is no need for us to take long over this. I think it will be sorted out as quickly as possible.

Regarding Afghanistan, as I have already said, we expressed our opinion. We tried to understand each other's opinion and that is where the matter rests.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1980-81—*Contd.*

MINISTRY OF DEFENCE—*Contd.*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं हाल ही में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का दौरा कर के आया हूं । अनेक समस्यायें वहां इस लिए उत्पन्न हुई हैं कि वह इलाका सीमा से लगा हुआ है ।

13.53 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*]

वहां जा कर मुझे लगा कि शायद हम उस सीमान्त को भूल गये हैं—वह हमारा विस्मृत सीमांत हो गया है । इस सदन में, और इस सदन के बाहर, हम उस क्षेत्र में विदेशी हाथ होने की बात करते हैं । लेकिन उस क्षेत्र को हम किस तरह से विदेशी हस्तक्षेप और विदेशी प्रभाव से सुरक्षित करें, इसके बारे में जितनी गहराई से सोचा जाना चाहिए, हमने नहीं सोचा ।

समस्या का एक पहलू आन्तरिक है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा । लेकिन चीन, बर्मा और बंगलादेश से लगा हुआ, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, पूर्वांचल आज हमारे लिए एक विस्फोट का कारण बन रहा है । मैं उस पुरानी भूल में नहीं जाना चाहता जब

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हम ने तिब्बत को चीन का भाग स्वीकार कर लिया। चीन के साथ हम अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके साथ यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि तिब्बत की खोई हुई स्वायत्तता तिब्बत को वापस मिल जाये।

आज बंगला देश और बर्मा में ऐसे क्षेत्र हैं जहां के बारे में समाचार मिलते हैं कि हमारे कुछ लोगों को वहां सैनिक शिक्षा दी जा रही है। ये क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि जहां उन सरकारों का भी वश न चलता हो। लेकिन यदि हम इन देशों के साथ अपने मैत्री-सम्बन्ध बढ़ाएं तो ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है कि वहां से मिलने वाली सहायता बन्द हो जाय और अगर आवश्यकता पड़े तो भारत जैसे मित्र देश की मदद ले कर वह अपने देशों में जो भारत-विरोधी कार्य-वाहियों के अड्डे बन गए हैं, उन अड्डों को साफ करने में आगे बढ़ें। मैं नहीं जानता बर्मा में कुछ दिनों बाद स्थिति क्या होगी। यदि बर्मा गुट-निरपेक्षता के रास्ते से डगमगाता है और बर्मा में ऐसे तत्व जोर पकड़ते हैं जो विदेशों द्वारा न केवल प्रभावित हैं, किन्तु नियंत्रित हैं, तो हमारे लिए उस क्षेत्र में कठिनाई बढ़ेगी।

इस सम्बन्ध में जब पूर्वांचल की चर्चा हो रही है तो चलते चलते मैं एक बात कह दूं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना का अधिकाधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति को हमें दबाना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है। सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए है। सेना शत्रु का सामना करने के लिए है और उस का सफाया करने के लिए है। आज हम फ्लैग मार्च के लिए सेना को बुलाते हैं। आज उस का एकदम असर होता है मगर कल वह असर उस से कम होगा, परसों और भी कम होगा। हम इस तलवार की धार को भोंथरा करने की गलती न करें। सेना सड़कों पर मार्च करने के लिए नहीं है। पुलिस अपना काम करे, सेना अपना काम करे। मैं जानता हूं कि अनिवार्य परिस्थिति में फैसले लिए जाते हैं लेकिन हमें इस बात का अधिकाधिक ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह बात केवल पूर्वांचल पर लागू नहीं होती, सारे देश पर लागू होती है।

जब हम रक्षा मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर विचार करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम यह प्रश्न पूछें कि आठवें दशक में हमारी रक्षा की आवश्यकताएं क्या होंगी? आवश्यकताओं को हमें उन की समग्रता में देखना होगा। हमें इस बात का भी विचार करना होगा कि हमारे सामने खतरे क्या हैं, थ्रेट परसेप्शन क्या है? मैं वाद-विवाद में कल उपस्थित नहीं था लेकिन जो मैंने कार्यवाही की रिपोर्ट पढ़ी है उससे मुझे लगता है कि हम समस्याओं को टुकड़ों में देख रहे हैं। देश की लोक सभा रक्षा मामलों सम्बन्धी सारी बहस को इन मुद्दों पर केन्द्रित कर दे कि हम ऐटम बम बनाएं या न बनाएं, जगुवार खरीदें या न खरीदें तो यह ठीक नहीं होगा। मेरा निवेदन है ये छोटे प्रश्न हैं, इन पर फैसले करिए। मेम्बर राय प्रकट करें। .... (व्यवधान) .... प्रधान मंत्री अगर कहें कि ये बड़े प्रश्न हैं तो मैं मान लूंगा। (व्यवधान) ... ये प्रश्न अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हुए भी सारे रक्षा के सवाल पर विचार करते समय ऐसे नहीं हैं कि ये प्रश्न सदन पर और बहस पर हावी हो जाये।

14.00 hrs.

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर): उल्लेख होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उल्लेख आवश्यक है। डाक्टर साहब अवश्य उल्लेख करेंगे, मैं जानता हूं। मैं भी एटम बम का काफी उल्लेख किया करता था। मैं कल सदन में था नहीं, गाडगिल साहब ने कह दिया कि वाजपेयी देशाभिमान और एटमबम की बात करते थे, अब एटम बम की बात नहीं करते तो देशाभिमान कहां गया? क्या देशाभिमान एटम बम के साथ जुड़ा हुआ है?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): आप ही जोड़ते थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: देशाभिमान के साथ नहीं जोड़ते थे। मगर हम जो पहले करते थे क्या वही अब आपने करने का फैसला कर लिया है।

श्रीमती इंदिरा गांधी: नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अगर पाकिस्तान एटम बम का निर्माण करता है तो इस भू-खण्ड में नई परिस्थिति पैदा होगी, उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मैं उन लोगों में से हूं कि जो इस मामले में सारे दरवाजे खुले रखने के पक्ष में हैं लेकिन सारी बहस को इस मुद्दे पर केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है इसलिए हम भी एटम बम बनायें। चीन ने एटम बम बनाया लेकिन हमने एटम बम का निर्माण नहीं किया और एटम बम से सुसज्जित चीन से उत्पन्न संकट का हम सामना करते रहे हैं। पाकिस्तान एटम बम बनायेगा तो हम भी बनायेंगे फिर यह भी तय करना पड़ेगा कि पहले एटम बम कौन चलायेगा? हम तो नहीं चला सकते। चीन भी कह रहा है कि वह पहल नहीं करेगा। अगर हम पहले एटम बम नहीं चलायेंगे तो निर्णय करना होगा कि पाकिस्तान के एटम बम के प्रहार के बाद हम एटम बम चलायें, तो एक सेकेण्ड स्ट्राइक कैपेसिटी का हमें विकास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इन सारे सवालों पर बहस हो, पूरी तस्वीर सामने रखी जाए। मैं उसमें और जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान का उल्लेख हुआ है बहस में। सवाल यह है कि पाकिस्तान का खतरा क्या उसके इरादे के कारण

है या उसकी क्षमता के कारण है ? पुराने अनुभव अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान को मिलने वाले हथियार भारत के विरुद्ध काम में लाए गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान में रूस के सैनिक हस्तक्षेप से इस भूखण्ड की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है और हमें पाकिस्तान के बारे थोड़ा देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान—यह तीनों उथल-पुथल से ग्रस्त हैं। इस उथल-पुथल के पीछे अगर बड़ी शक्तियां न होतीं तो शायद हमारे लिए यह उतनी चिन्ता का कारण नहीं था। लेकिन बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए सक्रिय है। चीन भी महा-शक्ति होने के लिए दरवाजे खटखटा रहा है। लेकिन हम इस बात को न भूलें कि अपने बल पर हम भी एक शक्ति हैं इस क्षेत्र में और आत्म-विश्वास के आधार पर रक्षा और विदेश नीति की समन्वय करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें।

इस बहस में यह चर्चा की गई है कि हमें नौशक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम पनडुब्बियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन प्राप्त करने से पहले ही देश में गहस शुरू हो गई। आज ही जागगुआर के बारे में ब्रिटेन की प्रधान मंत्री ने कुछ कहा है। मेरा निवेदन है कि पुरानी सरकार जो फैसला करे, मैं नही कहता उन्हें बदलने का वर्तमान सरकार को अधिकार नही है, लेकिन इन मामलों में एक कण्टीन्यूटी की आवश्यकता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : देश के हित में हो तभी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर राष्ट्रीय हितों का ध्यान नही रखा गया, इस देश के लोगों ने ऐसी सरकार चुन दी जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा नही कर सकती थी, उस सरकार को चलाने वाले कुछ प्रमुख लोग ऐसे थे ....

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : आज के अखबार में उस सरकार को चलाने वाले का स्टेटमेंट पढ़े, जिसमें ढाई करोड़ के असम को एक नेशन कहा है, तो ऐसे सरकार चलाने वालो को ....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री नरसिंह राव जी यहां बैठे हुई हैं, आन्ध्र में आन्ध्र को राष्ट्र कहा जाता है। तेलगू में प्रदेश के लिए राष्ट्र शब्द है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसमे क्या है। यहां तो महाराष्ट्र भी है। ...(व्यवधान) ....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शब्दों पर लड़ाई मत करिए। सभापति जी, आपको मुझे समय ज्यादा देना होगा। मैं टोका-टाकी करना पसन्द करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत गम्भीर बात कही है, अगर उनका यह आरोप है कि जो पिछली सरकार थी ...

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रही हूं।

.. (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, हमको तो बोलने नही देना चाहते हैं और प्रधान मंत्री को भी बोलने से रोक रहे हैं।

सभापति जी, मेरा निवेदन है कि हम जब नौसेना की बात करते हैं, तो हमारा कान्सैप्ट क्या ब्लू-वाटर-नेवी का है या हमें ऐसी नेवी चाहिए जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके, हमारे तटीय व्यापारिक ढांचे को सुरक्षित रख सके। हिन्द महासागर तो बड़ी शक्तियो का अखाड़ा रहने वाला है। हम उसे शान्ति का सागर बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न कर रहे हैं। उन प्रयत्नों में हमें तेजी लानी होगी, लेकिन हमें वस्तुस्थिति को समझना पड़ेगा। इस क्षेत्र को बड़ी शक्तियों का दंगल बनाने से कैसे रोकना है, इसकी ओर देखना चाहिए। जब हम अफगानिस्तान की बात करते है, अफगानि-स्तान के बारे में चिन्ता प्रकट करते है और सरकार की नीति की आलोचना करते है, तो इसके भूल में भी यही भावना है कि अगर एक बड़ी शक्ति इस भू-खण्ड में विस्तारवाद का परिचय देगी तो और शक्तियों को परिस्थिति का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। हमें इस भूखण्ड को बड़ी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखना है। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया, विदेश नीति और रक्षा की नीति का मेल आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि हम देखे कि रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे मे डिफेंस सर्विसेज में जो काम हो रहा है, वह ठीक है या नहीं।

सभापति जी, मेरा समय सीमित है।

सभापति महोदय : आपके लिए बहुत थोड़ा समय था, लेकिन 15-20 मिनट तो अभी हो गए है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : थोड़ा सा आप और उदार हो जाइए।

सभापति महोदय : आप को जो भी कहना हैं, आप थोड़े से शब्दों में भी कह सकते है, इस बात की मुझको जानकारी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर टोका टाकी न होती तो मैंने अभी तक खत्म कर दिया होता।

सभापति जी, दिल्ली से प्रकाशित यह मेरे पास एक अखबार है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट-पैटीशन पेश की गई थी, करने वाले शायद हमारे कोई एक्सपर्ट है। पत्र ने लिखा है :—

"He listed many instances of corruption in the Directorate of

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

Aeronautics. The court however ruled that it was not competent to go into the charges and neither did it have the required expertise."

कोर्ट का फैसला ठीक है । लेकिन अगर डिफैंस और रिसर्च में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्हें अनुसंधान करने से रोका जा रहा है, तो यह बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है अभी तक हमें एण्टी-टैंक-मिसाइल नहीं बना सके हैं, क्यों नहीं बना सके हैं, इसकी चर्चा 1960 से चल रही है, बीच में दावा किया गया था कि मिसाइल बन गया, लेकिन पता लगा कि नहीं बना है । हम हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, लड़ाकू हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, कौन से जहाज खरीदें—इस पर बहस हो रही है । लेकिन हम अपने देश में इस तरह के जहाज क्यों नहीं बना सकते, अब तक क्यों नहीं बना पाये ? रिसर्च एण्ड डवेलपमेंट विंग में जिस तरह से काम होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस तरह काम नहीं हो रहा है ? कहीं हमारे तरुण वैज्ञानिक निराश तो नहीं हो रहे हैं ? कहीं ऐसे अफसर तो नहीं बैठे हैं जो विदेशों से सामान खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर रक्षा सामग्री खरीदने में उन के निहित स्वार्थ रहते हैं ? इन सब बातों की जांच होनी जरूरी है ।

अभी हम टैंक खरीदने जा रहे हैं । विजयंत टैंक जब हम ने बनाया था, उस की बहुत प्रशंसा हुई थी, उस से हम कितना आगे बढ़े हैं, अगर नहीं बढ़े हैं तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं ? फौज पर रुपया खर्च करने में यह सदन कभी कोताही नहीं करेगा, लेकिन फौज की शक्ति संख्या में नहीं है, उस की प्रभावशालिता में है और उस की वह प्रभावशालिता बढ़नी चाहिये —जमीन पर, आसमान में और समुद्र में । इस पर विचार करते हुए हम यह भी सोचें कि खतरा कहां से है और खतरे का किस तरह से सामना किया जा सकता है ।

मगर मुझे अफसोस है, सभापति महोदय, एक बात कह कर मैं खत्म कर दूंगा । वाद-विवाद हो रहा है और प्रधान मंत्री जी सदन में बैठी हुई है, उन को बैठना पड़ रहा है, अगर कोई रक्षा मंत्री होता तो शायद वह अपना समय कुछ और महत्वपूर्ण कामों में लगा सकती थीं । 6 महीने हो गये इस देश का कोई रक्षा मंत्री नहीं है ... मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस (आई) के पास कोई ऐसा सदस्य नहीं है, जो डिफेन्स मिनिस्टर बन सके । मगर अभी तक रक्षा मंत्री नहीं है, पूरा समय दे कर काम करने वाला रक्षा मंत्री नहीं है ।

मुझ से एक गलती हो गई थी—नरसिंह राव जी यहां बैठे हुए हैं, इस लिए मैं उस का स्पष्टीकरण कर दूं । मैं चुनाव सभा में भाषण देने के लिए उदयपुर गया था । वहां पर मैंने यही मुद्दा उठाया था—मैंने कहा था कि अगर प्रधान मंत्री जी चाहें तो सुखाड़िया जी को रक्षा मंत्री बना सकती हैं । किसी समाचार समिति ने रिपोर्ट दी कि वाजपेयी ने कहा है कि नरसिंह राव को हटा देना चाहिए और सुखाड़िया जी को विदेश मंत्री बना देना चाहिए । मैंने उस का खण्डन किया तो किसी ने छापा नहीं । विदेश मंत्री जी जरूर मुझ से नाराज होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के पास पूरा समय दे कर काम करने वाला रक्षा मंत्री होना चाहिए । प्रधान मंत्री जी ऊपर से देख भाल करें ... (व्यवधान) ... वे तो सारे मंत्रालयों की देख-रेख कर रही हैं । मगर यह पार्ट-टाइम काम नहीं है और देश की रक्षा की समस्याओं को पार्ट-टाइम आधार पर हल नहीं किया जा सकता है ।

14.v3 hrs.

STATEMENT *RE.* LAUNCHING OF SLV-3

MR. CHAIRMAN: The Hon. Prime Minister wants to make a statement.

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, I want to share some good news with you and the hon. Members.

I have pleasure in informing the House that the first successful launch of the Indian Satellite Launch Vehicle SLV-3 took place this morning at 8.03.45 hours from Srihariketa Range. The Launch Vehicle placed a 35 kg. India Satellite Rohini RS-I in orbit around the earth. The Satellite will orbit the earth approximately once every 90 minutes. SHAR will see two orbits for the first time tonight. Thereafter every twelve hours two more such orbits will be seen over SHAR in regular periodicity.

The four-stage all solid-propellant vehicle has been developed in India by Indian scientists and Engineers. The total development cost of the SLV-3 Vehicle is about Rs. 20 crores and the present experimental launch has cost about Rs. 1 crore. The Rohini satellite in orbit is intended mainly to measure the performance parameters of the Vehicle and is being tracked by our National Tracking network. Initial indications are